उड़ान भरती आर्थिकी

आनंद मिश्र • लखनऊ

तीन दिन का मेला और देश-दुनिया के उद्योगपति एक मंच पर। बीते फरवरी की 10, 11 व 12 तारीख को लखनऊ में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जब एक ही दिन में 10 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतरे तो यह सरकार के उन प्रयासों का सुफल था जो पिछले सात सालों से उद्यमियों का भरोसा जीतने के लिए किया जा रहा था। एक ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था व सरकारी विभागों की जटिलताओं से उद्यमी आने में घबराते थे, वह अब व्यवसाय मित्र के रूप में सामने था। प्रदेश की आर्थिकी को पूरे देश में शिखर पर ले जाने के लिए मजबूत नींव रखी जा चुकी है। उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा ही।

समग्र प्रयासों ने उप्र में यह वातावरण पैदा किया है और 'बीमारू प्रदेश' की संज्ञा हटाई है। हर सेक्टर में काम दिखाई देता है, वह चाहें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यातायात कनेक्टिविटी हो, या फिर बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य व शिक्षा। आंकड़े बताते हैं कि यूपी की 56 प्रतिशत आबादी कामकाजी है। प्रदेश न केवल 250 मिलियन की आबादी वाला राज्य है, बल्कि 425 मिलियन के आस पड़ोस के राज्यों की जनसंख्या के साथ विशाल उपभोक्ता आधार भी रखता है। निवेशकों को ऐसा ही बाजार चाहिए भी, लेकिन पहले वे कनेक्टिविटी के अभाव और कानून व्यवस्था के नाम पर हिचक जाते थे।

कनेक्टिविटी का बड़ा जाल

बीते सात साल में कनेक्टिविटी एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य में विकसित हो रही वायु, सड़क, जल एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी ने उद्यमियों का बड़ा संकट खत्म किया है। निर्माण इकाइयों को अपने माल के परिवहन में अब असुविधा नहीं। निर्यात यदि बढ़ा है तो बड़ा योगदान इसका है। वायु परिवहन में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद प्रदेश में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो चुके हैं। जल्द ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी प्रारंभ होने वाला है। इसके बाद यूपी पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। यही वजह है कि ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लाजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स 2023) रैंकिंग में यूपी ने 'अचीवर्स' की श्रेणी हासिल की है।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए चलाई गई मुहिम

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और पटरी पर लाने के लिए मिशन मोड में कार्य शुरू करने के साथ ही राज्य सरकार ने नौजवानों को हर हाल में रोजगार से जोड़ने की मुहिम भी शुरू की, जिसके लिए जरूरी था कि अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी था कि सरकार की नीतियों से जटिलताएं खत्म हों।

उन नीतियों को चिह्नित किया गया जो उद्यमियों के लिए समस्या बनती थीं और 25 से ज्यादा सेक्टोरियल पालिसी बनाकर उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को आकर्षित करने के लिए अलग से नीतियां बनीं। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे का तेजी से विकास और इनके किनारे 46 हजार एकड़ का लैंड बैंक मील के पत्थर हैं।

सफलताओं ने बदली धारणा

प्रदेश आज भारत के टाप-5 मैन्यूफैक्चरिंग स्टेट में शामिल हो चुका है, जिसके पास 86 लाख से अधिक एमएसएमई का विशाल क्लस्टर है। यह भारत में किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। एक्सप्रेसवे और कारिडोर के किनारे जमीन की उपलब्धता औद्योगिक जगत के लिए और अवसर बढ़ाएगी। सरकार पालिसी बेस्ड गवर्नेंस की छवि पर काम किया है जो उद्योग जगत के लिए जरूरी थी।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-4.0

- 2016-17 में प्रदेश का बजट जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये का था वहीं 2024-25 का बजट इसके दोगुणे से भी अधिक 7.36 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है।
- 2016-17 में प्रदेश का सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जीएसडीपी) 12.75 लाख करोड़ रुपये था, इसकी तुलना में 2024-25 की सकल घरेलू उत्पाद 25 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। उप्र देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुका है।
- 50 से अधिक आयोजनों से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। यूपी में विगत एक साल में 44 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जो अबतक का रिकार्ड है।

बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत लिए महत्वपूर्ण निर्णय

उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने न केवल 41 विभागों के 481 लाइसेंस सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ला दिया है, बल्कि 13 लाख से अधिक लाइसेंस आवेदनों का भी जल्द से जल्द निस्तारण किया। बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (बीएआरपी) के अंतर्गत एक हजार से अधिक निर्णय किए गए। दूसरे अन्य रोड़े भी दूर किए गए। 200 से अधिक सेवाओं में तय समय में एनओसी प्रदान करने की व्यवस्था की गई। प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना जिसने प्रदेश एक ट्रिलियन इकोनामी के लक्ष्य का आधार बनाया।